

दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी धार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई कडारगा बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था।

14.59 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 6-4-83 को केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। परन्तु अभी तक कोई माकूल हल नहीं निकला।

यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को या तो खुद जल्दी से जल्दी हल करे या तुरन्त से तुरन्त जलस्रोत कॉमिल नेशनल वाटर रिसोसिज काउंसिल में रखा जावे और राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा किया जा सके।

15.00 hrs.

(iv) Demand for railway facilities in Bidar district of Karnataka.

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी (बीदर) : बीदर रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म नं० 1 से 2 पर जाने आने के लिए ओवर ब्रिज प्लेट फार्म नं० 2 पर छत तुरंत करने की आवश्यकता है। साथ ही इस रेलवे बड़ी लाइन पर सिकंदराबाद-परली गाड़ी चलती है, जो कि बहुत ही धीमी गति से चलती है। बीदर से हैदराबाद सिर्फ 130/150 किलोमीटर के भीतर है और पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय लगता है। बीदर में हवाई दल का ट्रेनिंग

स्कूल है। साथ ही व्यापार और धार्मिक पवित्र स्थल के कारण यात्रियों का आना जाना ज्यादा है। यात्रियों की जरूरत को ख्याल में रखते हुए एक जल्दी रेल सिकंदराबाद से बीदर जारी करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से हैदराबाद, बंगलोर, दिल्ली, मद्रास तथा हिन्दुस्तान के हर कोने में आने जाने वालों को सुविधा होगी।

(v) Resettlement of Ex-servicemen in Vajay Nagar, Arunachal Pradesh.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Following the discovery of the Lissus and Yobins of Chinese origin living in the sensitive area of Vijaynagar in Tirap district of Arunachal Pradesh, especially after the conflict with China in 1962, government was keen to neutralise the deep penetration of these foreign tribals by resettling the families of ex-servicemen in that area. Strong inducements like allotment of upto 50 acres of land per family for cultivation and housing, besides other facilities including free air lift upto Mohanbari were accordingly offered to ex-servicemen and about 200 families of former Assam Rifles personnel were settled in the area.

These former armed forces personnel are however now very unhappy for they feel neglected and let down because of non-fulfilment of the assurances given to them both by the Central and local governments. While the foreign tribals are no longer confined to Gandhigram and are flourishing and spreading out encroaching upon the lands of the ex-servicemen the land for the ex-army personnels is yet to be demarcated and documented. While the ex-servicemen have no electricity and tap water facilities so far the foreigners are enjoying these facilities. The free air passage facility also has since been withdrawn.

Vijaynagar is a highly sensitive and strategic area with Burma on three sides.

I would therefore urge upon the government to accord top priority to the fulfilment of the promises given to them, namely

(i) allotment of upto 50 acres of land duly demarcated and documented; and

(ii) all-round development of Vijay-nagar area with all infrastructural facilities.

(vi) Need to propagate teachings of Sant Kabir.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : आज धर्म की आड़ में जो विष-वमन चल रहा है, वह समाज एवं देश को दिन प्रतिदिन विदीर्ण करता चला जा रहा है। धर्म के ठेकेदारों का उसकी वास्तविक मान्यताओं से दूर का भी रिश्ता नहीं रहता। इस देश में धर्म की आड़ में मेहनतकशों की अज्ञानता का जितना शोषण किया गया, उतना और किसी तरह से शायद नहीं हुआ। रूढ़िवादिता, कर्मकांड, पाखंड एवं अंधविश्वास आदि की संकुचित सीमाओं में जनसामान्य को जकड़ दिया गया। ऊपरी ढकोसलों से भेद एवं अंधकार की भावना जड़वती होती गई। आज के संदर्भ में यह नितांत आवश्यक हो गया है कि इंसानों को समानता के धरातल पर लाकर उनके मन से धार्मिक विद्वेष एवं कलह समाप्त किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में हमें महात्मा कबीर को याद करना होगा। लगभग दो माह पश्चात् संत कबीर का जन्म दिवस (ज्येष्ठ पूर्णिमा) भी आने वाला है। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। संत कबीर प्रथम कवि थे, जिन्होंने धर्म निरपेक्ष समाज की परिकल्पना की। उनकी साधना का सामाजिक पक्ष था। उन्होंने वास्तविक सुख पड़ोस के व्यवहार में माना। मानव सेवा उनके लिए सबसे बड़ी पूजा थी। अनुभूतियों पर आधारित उनका धर्म मानव धर्म था। उनकी सत्यवाणी चिरनवीन एवं शाश्वत है।

अतएव सरकार का परम कर्तव्य है कि समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों से जन सामान्य की मुक्ति के लिए संत कबीर की अभिव्यक्तियों को विभिन्न प्रचार एवं प्रसार के माध्यमों से अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए तथा उनके विचारों के विस्तारण को प्रोत्साहित करे। धर्म निरपेक्ष समाज के निर्माण में यह बहुत

बड़ा योगदान होगा। आज के संदर्भ में यह और भी अधिक सामयिक है।

(vii) Non-availability of Kerosene in rural areas.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : There is a very deep crisis of kerosene oil in the villages of several States of our country. People belonging to rural areas of U.P. are in great difficulty because they have not been getting kerosene oil for the last four or five months. Kerosene oil is the main source of light in our villages. It is really very unfortunate that kerosene oil which is one of the most essential commodities, is not available to the people who are in great need. Particularly, the students are the greatest sufferers. Therefore, I would like to suggest to the Government to make kerosene oil available to the people as quickly as possible. The present distribution system is mainly responsible for this crisis. I would also like to advise the Government to streamline the distribution system.

(viii) Early appointment of Chairman and Managing Director in Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : भारी इंजीनियरी निगम (एच० ई० सी०) रांची में विगत नौ महीनों से कोई अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नहीं है। इस बहुत बड़े सरकारी उपक्रम की व्यवस्था चौपट हो गई है। नौ महीने पहले जो इसके अध्यक्ष थे, उनके हटाए जाने के बाद अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। स्मरणीय है कि सेलेक्शन फार पब्लिक इंटरप्राइज बोर्ड ने बहुत पहले नाम की सिफारिश कर दी है।

इस बड़े भारी इंजीनियरी निगम की स्थापना 1957 में हुई थी। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक बड़े उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। उनके उद्देश्य थे : देश में स्टील प्लांटों के लिए यंत्रों का भारी मात्रा में निर्माण करना तथा देश की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन होने पर उसका निर्यात करना भी।